मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

जय काली कलकत्ता वाली
56 इंच की हवा निकाली

मोदी को दूसरा मौका मिलेगा या नहीं! 3
अवतार का प्रबन्धन कमज़ोर रहा 4
एक भयावह प्रेस कांफ्रेंस 5
ऑक्सीजन कांड की जांच में देरी 6
गांधी को गाली, गोडसे देशभक्त 8

वर्ष 32 अंक -27 फ़रीदाबाद 19-25 मई 2019 फोन -8851091460 2.50 ₹

राजकीय महिला कॉलेज का हाई- वोल्टेज ड्रामा

प्रोफ़ेसरों की गुटबाज़ी ने उल्लू सीधे करने में छात्राओं को बनाया हथियार

फ़रीदाबाद (म.मो.) बीते सप्ताह भर से सेक्टर 16 ए स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय में छात्राओं के यौन शोषण को लेकर जो हाई-वोल्टेज ड्रामा चलाया जा रहा है उसमें छात्राओं के हितों की सुरक्षा की अपेक्षा प्रोफ़ेसरों व प्रिंसिपलों के विभिन्न गुट अपने-अपने उल्लू सीधे करने की जुगत बिठाने में जुटे हैं।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस मामले में एक छात्रा ने प्रिंसिपल नरेन्द्र को दरखास्त देकर सूचित किया है कि जगदेव नाम का लैब सहायक व क्लर्क के तौर पर काम कर रहा चपरासी विक्रम किस तरह से छात्राओं को परीक्षा में पास कराने के नाम पर पैसे व यौन शोषण की मांग करते हैं। इसके लिये वे मैगपाई होटल में कमरा बुक कराने तक की बात कहते हैं।

30 अप्रैल को प्राप्त हुई इस शिकायत के आधार पर प्रिंसिपल ने जांच के लिये पहले तीन सदस्यीय कमेटी बनाई लेकिन आपसी गुटबंदी को देखते हुए इसमें दो सदस्य और बढ़ा दिये गये। ये पांचो इसी कॉलेज की महिला प्रोफ़ेसर नम्रता, जसविंदर, अमिता, रितिका गुप्ता व अर्चना वर्मा हैं। व्यापक गुटबंदी के चलते जांच रिपोर्ट को अपने-अपने हिसाब से प्रभावित करने के चक्कर में कमेटी 15 मई तक भी कोई रिपोर्ट न दे सकी। इस बीच मामला उड़ता हुआ चंडीगढ तक जा पहुंचा। वहां से कड़ी फ़टकार लगने के बाद 16 मई को दी गयी रिपोर्ट को 15 मई में दिखाया गया।

छात्रा की मूल शिकायत में उक्त दो आरोपितों के अलावा किसी का भी नाम नहीं है। परन्तु बाद में, जांच के दौरान कॉमर्स के एक प्रोफ़ेसर चन्द्रशेखर वशिष्ठ का नाम जोड़ते हुए यह कहा गया है कि उक्त दोनों आरोपितों ने छात्राओं से यह कहा था कि वे वशिष्ठ सर से सिफ़ारिश करके उन्हें पास करा देंगे। शिकायत में जिस छात्रा का ज़िक्र आता है वह विज्ञान संकाय की है न कि कॉमर्स की, ऐसे में कॉमर्स प्रोफ़ेसर द्वारा उसे पास कराने वाली बात भी संदेह पैदा करती है।

प्रोफ़ेसर वशिष्ठ के विरुद्ध एक अन्य शिकायत सेक्टर तीन बल्लबगढ निवासी उमेश शर्मा ने प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक कई जगह कर रखी है। फ़ोन पर पूछने पर उमेश ने इस संवाददाता को बताया कि उनकी भतीजी इसी महिला कॉलेज में कॉमर्स की पढाई कर रही है। उनका आरोप है कि प्रोफ़ेसर वशिष्ठ छात्राओं को ट्यूशन पढने के लिये विवश करते हैं। वे कॉलेज में ही ट्यूशन क्लासें लगाते हैं। जो छात्रायें उनसे ट्यूशन पढती हैं, उन्हें तो वे पास कर देते हैं जो नहीं पढती उन्हें फ़ेल कर देते हैं। ''परीक्षा का आयोजन, पर्चे जांचने व फ़ेल-पास करने का काम तो यूनिवर्सिटी करती है तो प्रो. वशिष्ठ कैसे कसी को फ़ेल-पास कर सकते हैं?'' जवाब में उमेश कहते हैं कि यूनिवर्सिटी नहीं वशिष्ठ ही फ़ेल पास करता है। खैर जो भी हो उमेश की शिकायत केवल जबरन ट्यूशन पढाने तक ही सीमित है न कि किसी प्रकार के यौन शोषण की।

पांच सदस्यीय जांच कमेटी में से एक प्रो. नम्रता भी हैं जिनका प्रो.वशिष्ठ के साथ काफ़ी अर्से से छत्तीस का आंकड़ा है। विभाग प्रमुख के नाते वशिष्ठ उन्हें गणित पढाने के लिये कक्षायें आवंटित नहीं करते थे क्योंकि उनका मानना है कि उन्हें गणित आता ही नहीं, इसलिये जब भी उन्हें गणित की कक्षा दी गयी छात्राओं का विरोध सामने आया है। वशिष्ठ के मुताबिक इसी के चलते बदले की भावना से नम्रता ने उनका नाम इसमें घसीटा होगा।

नम्रता जैसा ही मामला एक अन्य प्रो. रूपम डोरा का है जो कॉमर्स पढाने के लिये क्वालिफ़ाइड न होते हुए भी कॉमर्स विभाग में पहले बतौर गैस्ट और अब नियमित प्रोफ़ेसर तैनात हो चुकी हैं। इन्हें भी वशिष्ठ कॉमर्स की कक्षायें नहीं देते थे। इसी चक्कर में करीब 10 साल पहले रूपम डोरा ने वशिष्ठ के विरुद्ध एक शिकायत दायर की थी। उस वक्त से डोरा और नम्रता अपने साझा दुश्मन वशिष्ठ से भिड़ने का कोई मौका नहीं छोड़तीं। जानकार बताते हैं कि डोरा की नियुक्ति को लेकर अभी भी कुछ विभागीय पूछताछ जारी है।

चर्चा यह भी है कि 23 मई के बाद बड़े पैमाने पर प्रोफ़ेसर व प्रिंसिपलों के तबादले होने हैं। इसलिये कई लोग घात लगाये बैठे हैं कि अच्छा स्टेशन मिल जाये। दीपक विनायक हैं जो कि महिला कॉलेज नचोली की प्रिंसिपल हैं लेकिन फ़िलहाल वे इसी (सेक्टर 16 ए वाले) कॉलेज में ही बैठ कर अपना नचोली कॉलेज चलाती हैं। इस साल उन्हें नचोली जाना पड़ेगा लेकिन उनका प्रयास है किसी तरह उनकी तैनाती सेक्टर 16 ए वाले में ही हो जाय। इसके लिये मौजूदा प्रिंसिपल को भी यौन शोषण मामले में लापरवाही बरतने के लिये लपेटा जाये।

केवल दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के विरुद्ध मामला उठाने से न तो खबर सनसनीखेज बनती थी और न ही प्रशासन पर कोई दबाव बनने की आशा थी। इस लिये पूरे मामले को हाई-प्रोफ़ाइल एवं सनसनीखेज बनाने के लिये प्रोफ़ेसर वशिष्ठ को लपेटने का बेहूदा प्रयास किया गया। मामले को उछालने के लिये तिगांव स्थित सरकारी कॉलेज से लड़कों को भेज कर जिस तरह से प्रदर्शन को प्रायोजित किया गया उस से भी सिद्ध होता है कि मौजूदा प्रिंसिपल को बदनाम करके यहां से भगाया जा सके ताकि सीट खाली हो। कहा जा रहा है कि तिगांव के कार्यवाहक प्रिंसिपल की भी दिलचस्पी सेक्टर 16 ए कॉलेज में ही आने की है।

इस बीच राज्य महिला आयोग की कॉलेज में पूछताछ के बाद 16 ए स्थित सेन्ट्रल जोन के महिला थाने में प्रोफ़ेसर वशिष्ठ सहित तीनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 354 ए, डी व 34 आईपीसी के तहत एफ़आईआर दर्ज हो गयी है

छात्राओं को लचर व्यवस्था के भरोसे न रह कर खुद निपटना होगा

सीएस वशिष्ठ : गुटबंदी का शिकार?

जिस कॉलेज में पेड़ कटवा कर लाखों रुपये की लकड़ी बेच खाने वाली तत्कालीन प्रिंसिपल भगवती राजपूत व उसके प्यादे क्लर्क चमन लाल का कुछ न बिगड़ा हो, जिस कॉलेज में अनेकों बार छात्राओं द्वारा अनियमितताओं व घूसखोरी के खिलाफ़ प्रदर्शन करने के बावजूद किसी दोषी का कुछ न बिगड़ा हो वहां छात्राओं को अपनी सुरक्षा एवं हितों की रक्षार्थ गली सड़ी सरकारी व्यवस्था के भरोसे रहना भी नहीं चाहिये। महिला कॉलेज और महिला पुलिस स्टेशन का ढिढोरा पीटने वाली खट्टर सरकार के दम पर महिला सुरक्षित नहीं होगी।

पहली बात तो छात्राओं को पास होने के लिये अथवा कॉलेज व बाबुओं से काम निकलवाने के लिये शॉर्ट कट ढूंढने की बजाय अपने आप को मजबूत एवं सक्षम बनाना चाहिये तथा अपने अधिकारों को पहचान कर उनके लिये लड़ना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि कॉलेज प्रशासन कोई भी निर्णय करने में अपने आप को सक्षम नहीं पाता। वह हर काम के लिये 300 किलोमीटर दूर चंडीगढ में बैठे अधिकारियों पर निर्भर करता है। इतना ही नहीं वहां बैठे उच्चाधिकारी भी सत्ता के दलालों से आदेश पाकर ही कुछ करने या न करने का निर्णय लेते हैं। इन हालात में छात्राओं को सुसंगठित होकर संघर्ष का रास्ता अपनाना चाहिये।

मौजूदा मामले में भी जगदेव और विक्रम के खिलाफ़ इतनी शिकायतें एकत्र होने देना छात्राओं की कमज़ोरी सिद्ध करती है। इसके विपरीत होना तो यह चाहिये था कि उनकी पहली ही हरकत पर प्रिंसिपल को शिकायत करने के तुरंत बाद इनकी जूते-चप्पलों से पिटाई करके कॉलेज गेट से बाहर खदेड़ देना चाहिये था और कोई सरकारी दल्ला इनको पुनः कॉलेज में लाने का प्रयास करे तो उसकी भी जूतों से ही सेवा करनी चाहिये, ऐसे लोग तभी काबू आ सकते हैं।

प्रधानमंत्री, राहुल गांधी!

चुनाव प्रचार के गाली-गलौच भरे सरगर्म दौर में भी राहुल को कहते सुना गया कि वह सभी से सीखते हैं, मोदी से भी। 'कैसे नहीं शासन करना चाहिए', यही मोदी से सीखने को है। बतौर प्रधानमंत्री राहुल गांधी को इस टेस्ट का भी सामना करना होगा।

कांग्रेस के लिए बड़ी खबर है कि 2019 लोकसभा चुनाव में 'पप्पू' पास हो गया। लेकिन, फिलहाल, भाजपा के अन्दर खाते भी नहीं पता कि उनका 'फेंकू' झोला उठा कर जायेगा या नहीं। इसके लिए उन्हें भी 23 मई को आने जा रहे चुनावी नतीजों की प्रतीक्षा करनी होगी। 2014 चुनाव में मोदी के नेतृत्व में मिले पूर्ण बहुमत के आत्मविश्वास से छलकती पार्टी आज मोदी को लेकर भी असमंजस में दिखती है।

चुनाव का भविष्य अभी दावों और प्रति दावों में उलझा हुआ है। लेकिन यह तय है कि नरेंद्र मोदी यदि विदा लेंगे तो 'सबका साथ सबका विकास' की स्वयं निर्धारित कसौटी पर एक असफल प्रधानमन्त्री के रूप में। जबकि राहुल गांधी यदि प्रधानमन्त्री बने तो वे अपने पिता स्वर्गीय राजीव गाँधी के मुकाबले कई गुणा सफल प्रधानमन्त्री होने की राह पर चलने को स्वतंत्र होंगे।

'भारतीय राष्ट्र' बनाम 'हिन्दू राष्ट्र' के छाया युद्ध ने भी मोदी और राहुल को चुनावी रणनीति के दो विपरीत ध्रुवों पर खड़ा करने में योगदान दिया है; 'संकुचित' मोदी के मुकाबले में 'व्यापक' राहुल को नेतृत्वकारी भूमिका प्रदान की है। हालाँकि जहाँ आज मोदी का तरकश चले हुए तीरों से भरा हुआ है, किसान और मध्य वर्ग के लिए इन बेहद महत्वपूर्ण चुनावी नतीजों की पूर्व बेला पर, राहुल गांधी के संभावित प्रधानमंत्रित्व को परिभाषित कर सकने वाले तीन प्रस्थान बिंदु चिह्नित किये जा सकते हैं।

मनमोहन सिंह शासन में दस वर्ष की बैक सीट ड्राइविंग राहुल को वह राजनीतिक आत्मविश्वास नहीं दे सकी थी जो गत वर्ष तीन विधानसभाओं (मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़) में भाजपा को हराने के बाद से उनके हाव-भाव में आना शुरू हुआ। लेकिन नेपथ्य में बने रहने के उस लम्बे दौर के अंत में एक क्षण ऐसा भी आया जो राहुल में छिपे इस नैसर्गिक लक्षण के अनावरण जैसा था। सर्वोच्च न्यायलय ने सजा पाए विधायकों-सांसदों की विधानसभा-लोकसभा की सदस्यता समाप्त करने का निर्णय सुनाया ही था कि मनमोहन सरकार, राजनीतिक आधार पर, जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन का अध्यादेश ले कर सामने आ गयी। राहुल गाँधी ने नाटकीय अंदाज में कांग्रेस पार्टी की प्रेस कांफ्रेंस में प्रवेश किया और घोषणा की कि अध्यादेश को फाड़ कर फेंक दिया जाना चाहिए। अध्यादेश का यही हश्र हुआ और एक स्वच्छ राजनीति के पक्ष में खड़े दिखते पुरोधा का उदय भी।

अगले प्रस्थान बिंदु के रूप में उनके आरएसएस पर महात्मा गाँधी की हत्या का माहौल बनाने के सीधे आरोप को लिया जाएगा। आरएसएस की तमाम भभकियों और कोर्ट में घसीटे जाने के बावजूद, राहुल ने आरोप वापस नहीं लिए। अतिवादी साम्प्रदायिक राजनीति की मौजूदा परिस्थितियों में भारतीय राष्ट्र की एक सेक्युलर नुमाइन्दगी का बेलौस प्रमाणपत्र सरीखा परिदृश्य!

तीसरा प्रस्थान बिंदु था जब, तब तक ईमानदारी के अवतार के रूप में स्थापित किये जा चुके नरेंद्र मोदी को, राफेल खरीद के सन्दर्भ में, राहुल ने 'चौकीदार चोर है' के जुमले के साथ घेरा। अब तो यह जुमला सर्वव्यापी हो चुका है और नरेंद्र मोदी के शेष राजनीतिक कैरियर में उनका पीछा इससे छूटने वाला भी नहीं। राहुल की अपनी ईमानदार छवि का इससे अच्छा राजनीतिक बोनस और क्या हो सकता है। अगर आपको राम दिखना है तो एक अदद रावण तो चाहिए!

नेहरू, इंदिरा, राजीव के बतौर प्रधानमन्त्री शुरू के वर्षों को याद कीजिये। किसी प्रशासनिक अनुभव के अभाव में वे अपनी स्थितियों के मास्टर नहीं, उनके हाथों में खेलते ज्यादा नजर आते हैं। स्वयं नरेंद्र मोदी, अचानक गुजरात का मुख्यमंत्री बन जाने पर, मुख्यतः प्रशासनिक अनुभवहीनता के ही चलते, गोधरा ट्रेन काण्ड और गुजरात नरसंहार के आयामों के सामने एक बेबस प्रशासक से अधिक कुछ नहीं सिद्ध हो सके थे। इनके विपरीत, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जब प्रधानमन्त्री बने तो उनके पीछे प्रशासनिक अनुभव के कई दशक थे। इसीलिए, उनकी राजनीतिक दिशा से मतभेद रखने वालों में भी उनमें शुरू से ही प्रशासनिक संशय नहीं दिखेगा।

इस परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी को देखें तो उनके कई गुणा सफल प्रधानमन्त्री होने में विश्वास बनता है। उन्होंने न सिर्फ मनमोहन दौर में दस वर्ष प्रधानमन्त्री पद की बैक सीट ड्राइविंग के अनुभव में हिस्सा लिया है, बल्कि मोदी के प्रधानमंत्रित्व के पांच वर्षों में अपनी पार्टी और अपने परिवार के सर्वाधिक बुरे दौर में सामने से नेतृत्व भी प्रदान किया है। यहाँ तक कि दशकों बाद वे किसान, कामगार और मध्य वर्ग के हित में विश्वास से बोल सकने वाले एक स्वीकार्य कांग्रेसी नेता के रूप में सामने आये हैं। एक वाक्य में कहें, यदि उन्हें प्रधानमन्त्री बनने का मौका मिला तो वे पूरी तरह तैयार लगते हैं।